भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2932
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : श्रीअन्न का विकास

2932. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) श्रीअन्न के विकास को प्राथमिकता देने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एफएओ और यूएनएफसीसीसी ने यह स्वीकार किया है कि ये फसलें जलवायु अनुकूल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके विकास और प्रगति के लिए विशिष्ट कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और मूल स्वदेशी बीजों के संरक्षण और उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विशेष रूप से गुजरात राज्य में हुई प्रगति के बारे में विशिष्ट सूचना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपने मिलेट्स संबंधी नोडल संस्थान अर्थात भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद के माध्यम से श्रीअन्न की उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल किस्मों/हाइब्रिड को विकसित करने के लिए बुनियादी और कार्यनीतिक अनुसंधान कर रहा है, जिसमें पर्ल मिलेट (बाजरा), ज्वार, रागी/मंडुआ, फॉक्सटेल मिलेट (कांगनी/इटालियन मिलेट), कुटकी, कोदो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट (सावन/झंगोरा), प्रोसो मिलेट (चीना/कॉमन मिलेट) और ब्राउन टॉप मिलेट (कोरले) शामिल हैं। इसके अलावा, देश में उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास, किसानों/अन्य हितधारकों के बीच प्रौद्योगिकी प्रसार/अंतरण आदि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, आईसीएआर-आईआईएमआर, हैदराबाद राज्य मिलेट मिशनों में राज्य सरकारों के साथ ज्ञान साझेदार के रूप में काम कर रहा है और राज्य कृषि विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सहयोग से कई मिलेट सम्मेलन, मिलेट कार्निवल, मिलेट खाद्य महोत्सव, प्रदर्शनी स्टालों का आयोजन कर रहा है।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष (आईवाईएम) घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। देश में मिलेट (श्रीअन्न) के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गुजरात राज्य सहित सभी 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत पोषक अनाज (मिलेट) पर एक उप-मिशन क्रियान्वित कर रहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्य की विशिष्ट जरूरतों/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को अनुकूलता भी प्रदान करती है। राज्य राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) की मंजूरी से आरकेवीवाई के तहत मिलेट (श्रीअन्न) को बढ़ावा दे सकते हैं। गुजरात में श्रीअन्न (मिलेट) का उत्पादन वर्ष 2020-21 के दौरान 10.92 लाख टन से बढ़कर 2023-24 के दौरान 14.09 लाख टन हो गया है।

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर-एनबीपीजीआर), नई दिल्ली भारत में पादप आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए नोडल संस्थान है। एनबीपीजीआर स्वदेशी किस्मों सहित पादप आनुवंशिक संसाधनों के अन्वेषण, अधिग्रहण, संरक्षण, लक्षण वर्णन और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है। एनबीपीजीआर में राष्ट्रीय जीन बैंक है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीजों सहित पादप आनुवंशिक संसाधनों के 4.71 लाख एक्सेसन्स का विशाल संग्रह संरक्षित करता है।

******